be about Rs. 346 crores. Further, an important thrust area identified by NABARD for the year 1997-98 in the State of Maharashtra is the implementation of the Indo-German KFW Watershed Development Programme on grant basis with a financial assistance of DM 12 Million from Kreditanstalt Fur Wiederabubau (KFW). The programme of promotion of Self-Help Groups (SHGs) aimed at empowering the poorest of poor and undcrpriviledgcd in rural areas and linking them to banks is expected to be further accelerated during 1997-98. As on 31.10.97'2918 SHGs were linked to banks with a loan assistance of Rs. 104.76 lakhs and NABARD's refinance assistance of Rs. 91.85 lakhs. It is expected that about 3000 SHGs would be formed covering about 50,000 members in Maharashtra during the current year. In addition of these, the Maharashtra Rural Credit Project (MRCP) is being implemented since 1995 in four districts of the State in the first phase with IFAD's assistance.

NABARD provides loan assistance to State Governments under Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) for speedy competition of on-going projects relating to rural infrastructure. In the case of Maharashtra, NABARD has sanctioned loans to the State Government under RIDE-I & II, as follows:—

(Rs. in crores)

	No of Projects	Amount Sanctioned	Amount Utilised
RIDF-I	115	207.27	136.90
RIDF-II	108	231.66	96.30

Further, NABARD has so far sanctioned an amount of Rs. 139.06 crores to 361 projects pertaining to construction of rural bridges and rural roads in Maharashtra under RIDF-III.

बैंकों में जालसाजी के मामलों में वृद्धि

719. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है वर्ष 1990 में देश के बैंकों में जालसाजी के मामलों की संख्या 1559 थी जिनमें 65 करोड़ रुपये की हानि होने की संभावना थी और वर्ष 1995 में ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 1890 हो गई और इनके कारण 116 करोड़ की आर्थिक हानि का अनुमान था;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बैंकों में जालसाजी के मामलों की संख्या में वृद्धि के कारणों का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके निराकरण के लिए सरकार ने अभी तक क्या क्या प्रभावी कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) और (ख) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 के वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पता लगाए गए धोखा धड़ियों की संख्या और उसमें अंतर्ग्रस्त राशि से संबंधित सूचना नीचे दी गई है;

वर्ष	धोखाधड़ियों की संख्या	अंर्तग्रस्त राशि (लाख रुपये)
1990	1687	10593 +यूएस डालर 7500 +यूगांडा सिलिंग्स 4597789
1991	1559	6541
1992	1717	14449 +फिजियन डालर 1500
1993	2213	32032.43
1994	2246	20007.88 + यूगांडा सिलिंग्स 9844000
1995	1890	11551.12

धोखाधडियों के मामलों में अंतर्ग्रस्त राशि आवश्यक नहीं है कि वास्तविक हानियों को दर्शाते हों जो अन्ततः बैंक वहन करते है। सामान्यतया दिए गए अग्रिमों को कवर करने के लिए बैंकों के पास कुछ प्रतिभूतियां होती हैं। बैंक दीवानी (सिविल) और अपराधिक मुकदमें में दायर करते है और उपयुक्त राहत प्राप्त करते हैं।

(घ) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों में धोखाधड़ियों के मुख्य कारणों में ये है कि बैंकों में धोखाधड़ियों के मुख्य कारणों में ये सम्मिलित हैः निर्धारित प्रणाली और प्रक्रियाओं के अनुपालन, में परिचालन/पर्यवेक्षी कर्मचारियों द्वारा शिथिलता, बैंको द्वारा अपने ग्राहकों में अतिविश्वास, नियंत्रणों और अन्य समय-परीक्षित सुरक्षापायों में शिथिलता का लाभ उठाने वाले बेईमान व्यक्तियों (कर्मचारी, ग्राहक और अन्य) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुरोध पर धोखाधड़ियों को रोकने के लिए समय समय पर विभिन्न उपाय किये हैं। इन उपायों में ये सम्मालित हैः बैंकों में नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तृत आधार पर धोखाधडियों के मामलों की पुनरीक्षा, विशिष्ठ मामलों में उनकी कार्य प्रणाली के संबंध में बैंकों को जानकारी देते हुए उनकी पुनरावृत को रोकने के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपाय बताना, परिचालनात्मक कार्मिकों को उपयुक्त प्रशिक्षण और रिपोर्ट किये गए धोखाधड़ी के प्रमुख मामलों की जांच और संवीक्षा के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धोखाधडी बहुत क्षेत्रों में प्रणाली और नियंत्रण व्यवस्था को शामिल करते हुए आकस्मिक निरीक्षण।

New Scheme for filing Income tax returns

720. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have recently launched a new scheme for filing of Income Tax returns under new economic criteria by IT payers in a number of citities; if so, the details of the scheme and the names of cities; and

(b) whether IT payers living in satellite towns around Delhi namely Ghaziabad, Faridabad, Noida and Gurgaon come in the ambit of this scheme, and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATPAL MAHAJRAJ): (a) Finance Act, 1997, amended section 139 of Income Tax, 1961, providing for filing of returns of income in respect of persons who satisfy the requirements of ownership or use or expenditure on any two of the following four economic indicators:

(i) Ownershiplease of a motor vehicle;

(ii) Occupation of certain categories of notified immovable property whether by way of ownership of tenancy or otherwise;

(iii) Foreign travel; or

(iv) Subscription of a telephone. These provisions are applicable with ef fect from 01.04.97 in Urban agglomera tions of 12 citites which have been notified. These cities are Mumbai, Delhi, Chennai, Calcutta, Bangalore, Ahmedabad, Kanpur, Jaipur, Ludhiana, Hyderabad, Pune, Chandigarh including their urban agglomerations.

(b) Notified urban agglomeration of Delhi include State of Delhi, the areas comprised in Gurgaon Municipal Committee, the areas comprised in Faridabad Complex of District Faridabad, the areas comprised in Ghaziabad Municipality, the areas in the district of Ghaziabad notified by Government of Uttar Pradesh and regulated by Ghaziabad Development Authority and the areas notified by Government of Uttar Pradesh and regulated by New Okhla Industrial Development Authority (NOIDA).

Shortage of coins and currency notes

721. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the prevalent shortage of coins and small currency notes in the country causing much hardships to all sections of society;

(b) if so, the reasons therefor and remedies planned to meet the situation;